भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2605
उत्तर देने की तारीखः 18.03.2021

शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का हिस्सा

2605 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश को 2021-22 के लिए बजट में कार्यान्वित नहीं किये जाने का क्या कारण है;
(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यथापरिकल्पित जीडीपी व्यय के 6 प्रतिशत को कार्यान्वित करने का विचार रखती है;
(ग) यदि हां, तो 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल कर लिया जाएगा; और
(घ) महामारी के पश्चात् शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में बजट अनुमान (बीई) 2020-21 की तुलना में शिक्षा के लिए घटाए गए बजट आवंटन का क्या प्रभाव है और सरकार की इस वर्ष घटाए गए बजट के साथ किस तरह से कार्य करने की योजना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% का अनुशंसित स्तर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में परिकल्पित किया गया था। यह 1986 की नीति में दोहराया गया था और आगे भी इसकी फिर से 1992 में नीति की समीक्षा में पुष्टि की गई थी। भारत में शिक्षा पर मौजूदा सार्वजनिक (सरकार-केंद्र और राज्यों) व्यय जीडीपी का लगभग 4.43% (बजटीय व्यय का विश्लेषण, 2017-18) रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,

2020 ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों दोनों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन किया और इसकी परिकल्पना की। जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है, केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

(घ): 2020-21 के लिए शिक्षा मंत्रालय का बजट अनुमान 99311.52 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित कर 85089.07 करोड़ रुपये किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए बीई 93224.31 करोड़ रुपये है जो आरई 2020-21 की तुलना में 9.6% अधिक है। महामारी के बावजूद, यह सुनिश्चित किया गया कि शैक्षणिक वर्ष की बर्बादी न हो। शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों/ निर्देशों/ एसओपी के अधीन है।

******